

 सत्यमेव जयते	<b>राजस्थान राजपत्र</b> <b>विशेषांक</b>	<b>RAJASTHAN GAZETTE</b> <b>Extraordinary</b>
	<b>साधिकार प्रकाशित</b>	<b>Published by Authority</b>
	फाल्गुन 25, शुक्रवार, शाके 1945-मार्च 15, 2024 <i>Phalguna 25, Friday, Saka 1945- March 15, 2024</i>	

**भाग-1(ख)**

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

**वन विभाग**

विज्ञप्ति

**जयपुर, जनवरी 30, 2024**

**संख्या प. 2(47)वन/2024** :-चूंकि संलग्न अनुसूची में वर्णित वनभूमि एवं बंजर भूमि सरकार की सम्पत्तियाँ हैं या उनमें सरकार के स्वामित्व अधिकार हैं या उनकी सम्पूर्ण या आंशिक वन उपज पर सरकार का अधिकार है,

और चूंकि ऊपर कथित वनभूमि या बंजर भूमि को सरकार, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत संरक्षित वन के रूप में घोषित करने का विचार रखती है,

और चूंकि, पूर्वोक्त भूमि पर सरकार और निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि, सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या उस पर सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की सीमा एवं स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना एवं उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा कि इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचाने की आशंका रहेगी।

अब इसलिए, राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) की धारा 29 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वनभूमि या बंजर भूमि में या सरकार एवं निजी व्यक्तियों के अधिकारों की जाँच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है और ऐसी जांच, साक्ष्य एवं अभिलेख उस प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि इस अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11(2), 12, 13, 14, 17, 18 एवं 19 में प्रावहित है।

और, इस अधिनियम की धारा 29 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान सरकार ऊपर कथित जांच एवं अभिलेख के विचारार्थ रहते, कथित वनभूमि एवं बंजर भूमि को इस विज्ञप्ति के द्वारा संरक्षित (Protected) वन के रूप में घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों या वर्ग विशेष के वर्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और न ही उन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

और इस अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषणा करती है कि उक्त रक्षित वन के वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से आरक्षित (Reserved) हो जावेंगे और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में पत्थर खोदना या चूना या लकड़ी का कोयला जलाया जाना अथवा किसी भी प्रकार की वन उपज

का संग्रहण किया जाना या निष्कासन करना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि की खुदाई या कृषि हेतु या भवन निर्माण हेतु या मवेशी चराने या अन्य प्रयोजनार्थ वन की सफाई करना या वनभूमि को खण्डित किया जाना निषिद्ध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मोनाली सेन,

विशिष्ट शासन सचिव, वन।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि व बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

**प्रथम अनुसूची**

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	दिशा	दिशावार सीमा विवरण	राजस्व ग्राम	विवरण		
							खसरा नं.	क्षेत्रफल	खसरा नं.
1.	छोटाघाटा-ए	गिर्वा	उदयपुर	उत्तर	वनखण्ड छोटाघाटा	रायता	1016/1	4.6467 हैक्टर	मगरी
				दक्षिण	राजस्थान सरकार बिलानाम भूमि				
				पूर्व	वनखण्ड छोटाघाटा				
				पश्चिम	राजस्थान सरकार बिलानाम भूमि				
योग								4.6467 हैक्टर	

(विजेन्द्र सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
उदयपुर (पश्चिम)।

(सुगना राम जाट I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर।

द्वितीय अनुसूची  
पेड़ों की सूची  
वनखण्ड - छोटाघाटा- अ

क्र.सं.	बोटैनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	Butea monosperma (Lamk.) Taub	खाखरा
2	Wrightia tinctoria (Roxb.) R.Br.	खिरनी
3	Holoptelea integrifolia (Roxb.) Planch	चुरैल
4	Tectona grandis L. f. Suppl	सागवान
5	Prosopis Juliflora (Swartz) DC.	विलायती बबुल

(विजेन्द्र सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
उदयपुर (पश्चिम)।

(सुगना राम जाट I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर।

**प्रमाण-पत्र**

वन खण्ड - छोटाघाटा- अ

रेंज - रेंज उदयपुर पश्चिम

वन मण्डल - उप वन संरक्षक, उदयपुर

1. प्रारूप में दर्शाई गई भूमि आर्मी केम्पस पिपलिया निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले रायता तहसील गिर्वा की बिलानाम आराजी नम्बर 1016 रकबा 7.0100 है. किस्म मगरी में से आराजी नम्बर 1016/1 रकबा 4.6467 हैक्टेयर कुल कित्ता 01 रकबा 4.6467 है. भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा -92 के तहत वन विभाग के लिये आरक्षित की गई थी। जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में वन विभाग के नाम से अमलदरामद हो चुकी है। इस भूमि पर वन विभाग द्वारा वानिकीय विकास कार्य करवाये जाने हैं।
2. विज्ञप्ति प्रपत्र में उल्लेखित भूमि वन विभाग के अधीन है। प्रस्तावित भूमि में प्रथम दृष्टतया कोई अतिक्रमण, खनन कार्य नहीं किये हुए है।
3. प्रस्तावित वन क्षेत्रों में समस्त क्षेत्र विभाग के अधीन है, जिन पर वानिकीय विकास कार्य किये जाने हैं।
4. प्रस्तावित भूमि पर वृक्षों का घनत्व लगभग 0.20 प्रतिशत तक का है एवं इन क्षेत्रों में मुख्य सागवान, खाखरा, बबुल चुरेल व खिरनी प्रजातियों के पेड एवं झाड़ियां हैं।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की समस्त भूमि वन विभाग के अधीन है तथा समीपवर्ती खातेदारी भूमिया वन सीमाओं से पृथक हैं एवं इससे प्रस्तावित वन क्षेत्रों के संरक्षण में कोई अवरोध नहीं होगा। विभागाधीन भूमियों का विकास कार्यों में उपयोग होगा।
6. प्रस्तावित भूमि का मानचित्र संलग्न है।
7. खसरावार भूमि का मौके पर सुविज्ञ रूप से सीमाज्ञान नहीं होने के कारण अधिसूचना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे किन्तु अब सीमाज्ञान के पश्चात् प्रस्ताव प्रारूप बनाये जाकर प्रेषित किये जा रहे हैं।
8. इस वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

(विजेन्द्र सिंह)  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
उदयपुर (पश्चिम)।

(सुगना राम जाट I.F.S.)  
उप वन संरक्षक  
उदयपुर।

---

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।